

जज अदालत ~~अतिरिक्त जिला कलेक्टर~~ मुकाम ~~सुन्नु~~

सरकार जरी खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री जयसिंह यादव बनाम श्री राजेश कुमार तोतलानी पुत्र श्री मनोज कुमार

किस्म मुकदमा FSSAI नं. 43 सन 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.09.2022	यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 एवं नियम 2011 खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री जयसिंह यादव द्वारा पेश करने पर बाद जांच प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। गैरसायल की तलबी जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 22/09/2022 को पेश हो। अति. जिला कलेक्टर सुन्नु	
22.09.2022	पत्रावली पेश हुई। आवेदक उपस्थित। अनावेदक संख्या 2 स्वयं उपस्थित। मैंने खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत जबाब एवं बहस पर ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। अनावेदक/अभियुक्त संख्या 2 का कथन है कि वह अपनी फर्म ऋषि मसाला उद्योग के नाम से भुदोली रोड़ नीम का थाना सीकर में मसाले तैयार कर बाजार में सप्लाई करता है। अनावेदक संख्या 1 के यहां से लिये गये मसाले के सेम्पल में किसी प्रकार की मिलावट नहीं पाई गई है। केवल पाउच पर लिखावट में कमी रहने से मसाला मिस ब्रान्ड माना गया है। अतः उसे धारा 26 (2) (II) का दोषी नहीं माना जाये। हस्तगत प्रकरण प्रकरण में खाद्य विश्लेषक राज जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं० एल.एस./1546/एक्ट/2022/1536 दिनांक 22.04.2022 के अनुसार अनावेदक संख्या 1 के मनोज प्रोविजन स्टोर, मेन मार्केट, नगरपालिका के पास खेतड़ी से लिया गया खाद्य पदार्थ लाल मिर्च पाउडर का सेम्पल मिसब्रान्ड (Misbranded) पाया गया है। जो एफ.एस.एस.एस.ए की धारा 26 की उपधारा (2) (II) के उल्लंघन में आता है। चूंकि अनावेदक संख्या 1 ने अनावेदक संख्या 2 से लाल मिर्च पाउडर की खरीद का पक्का बिल सेम्पल लिये जाते समय प्रस्तुत किया था तथा अनावेदक संख्या 2 स्वयं निर्माता है। अतः प्रकरण में खाद्य पदार्थ लाल मिर्च पाउडर का सेम्पल मिसब्रान्ड (Misbranded) पाये जाने की स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अनावेदक संख्या 2 श्री ऋषिकेश जांगिड़ पुत्र श्री चिरंजीलाल, मै० ऋषि मसाला उद्योग, भुदोली रोड़ नीम का थाना, सीकर को खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 3(1)(zf)(C)(i) का दोषी मानकर प्रकरण में अनावेदक को 5000/- पांच हजार रुपये अर्थदण्ड/जुर्माने से दण्डित किया जाता है। उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बजट मद में 15 दिवस में जजिने चालान बैंक में जमा कराकर चालन की एक प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। अनावेदक की एक प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सुन्नु को भिजवाये। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अति. जिला कलेक्टर सुन्नु	